खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में लघु निवेशकों की भागीदारी

*125. **श्री सुषमा स्वराज :†**
श्री राम जठमलानी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में छोटे पूंजी निवेशकों की भागीदारी बढाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान से आग्रह किया है कि वह देश की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी का विकास करे जिससे छोटे शहरों तथा ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध कच्चे माल का प्रयोग कर वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिले ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त संस्थान को अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई है जिससे यह अपने दायित्वों का सुविधापूर्वक तथा यथाशीघ्र निर्वहन कर सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान को विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

---

*सभा में यह प्रश्न श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पूछा गया ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैंने अपने प्रश्न के भाग "ख" में यह जानना चाहा था कि क्या सकार छोटे कस्बों और गांवों में फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए सैन्ट्रल फूड टैक्नोलोजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को कोई तकनीक विकसित करने के लिए कह रही है और यदि कह रही है तो क्या उसके लिए उसने कोई अतिरिक्त धन इंस्टीट्यूट को मुहैया करवाया है ? मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने यह तो माना है कि उसने सैन्ट्रल फूड टैक्नोलोजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को यह तकनीक विकसित करने के लिए कहा है, लेकिन मेरा जो भाग "सी" कनैक्टेड सवाल था जिसमें मैंने अतिरिक्त धन का आंकड़ा जानना चाहा था, के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत इन्स्टीट्यूट को धन मुहैया कराया जाता है । मैं बड़े अदब से आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह जवाब देने का सही ढंग नहीं है । हमने एक स्पेसेफिक सवाल पूछा है कि क्या तकनीक विकसित करने के लिए आपने इंस्टीट्यूट को कोई अतिरिक्त धन मुहैया कराया है ? अगर कराया है तो कितना कराया है ? जवाब आ रहा है कि हम विभिन्न स्कीमों के तहत इन्स्टीट्यूट को धन मुहैया कराते रहते हैं । मंत्री महोदय , यह तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई इन्स्टीट्यूट चल रहा है तो उसको स्कीमों के तहत आप धन मुहैया कराते होंगे, लेकिन मैं स्पेसेफिकली जानना चाहती हूं कि छोटे कस्बों और गांवों में फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए जो तकनीक विकसित करने के लिए आपने इंस्टीट्यूट को कहा है क्या उसके लिए आपने किसी अतिरिक्त धन की व्यवस्था की है, क्या कोई बजट एलोकेशन किया है, और यदि किया है तो कितना किया है ?

SHRI TARUN GOGOI: Sir, you will be happy to know that we have already asked the CFTRI to develop low-cost technology to help set up small-scale industries and they have already developed a lot of low-cost technologies suitable for small-scale

industries. We have also given assistance to the CFTRI to the tune of Rs. 252 lakhs for R&D in different sectors.

श्रीमती सुषमा स्वराज : डिवैलप तो किया है, लेकिन मेरा तो सवाल फिर अनुत्तरित रह गया । मैंने तो पूछा था बजट एलोकेशन कितना है । अगर आपके पास आंकड़ा नहीं है तो आप सभापति जी से अनुमति मांग करके आंकड़ा बाद में भेज सकते हैं । मैंने स्पेसेफिकली सवाल पूछा है कि इस काम के लिए आपने कितना एडीशनल बजट एलोकेशन किया है और अगर किया है तो कितना किया है, एक आंकड़ा मैं जानना चाह रही हूं और वह आंकड़ा नहीं आ रहा है । सभापति जी, अगर आप चाहें तो निर्देश कर सकते हैं और मैं दूसरी सप्लीमेंटरी पूछ सकती हूं ।

SHRI VIREN J. SHAH: Mr. Chairman, perhaps you might like to ask the Minister...

MR. CHAIRMAN: I think, she is able to defend herself.

श्रीमती सुषमा स्वराज : न तो मेरे मूल प्रश्न में इसका जवाब आया है और मेरा मूल प्रश्न यह था कि इस तकनीक को विकसित करने के लिए क्या सरकार ने कहा है कि उसने उसके लिए एडीशनल बजट एलोकेशन किया है, अगर किया है तो कितना किया है । बड़ा वेग उनका जवाब आया है कि मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत पैसा दिया जाता है । दिस इज नो आंसर । अब पूछा तो अब भी नहीं दिया है । This is no answer, Sir.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, have you got the facts?

SHRI TARUN GOGOI: Sir, we have already made allocations, and out of that allocation I have given Rs. 252 lakhs. Sir, there is another project of Food engineering centres at CFTRI being implemented for which there is an amount of about five crores of rupees.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, यदि आप कहते हैं तो मैं पहला अनुत्तरित रह करके अपना दूसरा प्रश्न पूछ लेती हूं । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भारत ब्राजील के बाद दुनियां का सब से बड़ा फल और सब्जियों का उत्पादक देश है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि करोड़ों रुपये का फल अच्छी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण नष्ट हो जाता है, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि यदि फल पैदा होने वाली जगह पर इस तरह का उद्योग लगा दिया जाए तो फल को भी सड़ने से बचाया जा सकता है, फल उत्पादक को लाभ कमवाया जा सकता है और देश के बच्चों को भी पेप्सी कोला के बजाय स्वास्थ्यवर्दक फलों का रस पिलाया जा सकता है, तो देश का उद्योगपति इस तरह का उद्योग लगाने के लिए आगे आए इसके लिए आपने देश के उद्योगपतियों को क्या इंसेंटिव देने की योजना बनाई है ?

SHRI TARUN GOGOI: Sir, it is true that we process a little over one per cent of fruits and vegetables. But, due to certain measures that we have taken, the production of fruit and vegetable products has gone up by about 20 per cent per annum in the last 3 years. The number of the small scale food processing units has also gone up from 99,792 in 1988 to 1,93,000 today.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मंत्री जी, मेरा बड़ा स्पेसेफिक सवाल है, आपने मेरे प्रश्न के भाग "क" में यह कहा है कि आप स्माल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इसमें करवाना चाहते हैं, मैं केवल यह पूछ रही हूं कि आप स्माल इन्वेटर्स का पार्टिसिपेशन केवल कागज पर करवाना चाहते हैं या उसके लिए आपने कोई इनसेंटिव देने की योजना बनाई है ? अगर बनाई है तो दो-चार इनसेंटिव आप पढ़कर सदन को सुना दीजिए कि यह इनसेंटिव इस इण्डस्ट्री में देंगे । इतना सपाट और इतना सीधा सवाल है मेरा, कि स्माल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन करने के लिए आपने कौनसे इनसेंटिव की योजना बनाई है ?

SHRI TARUN GOGOI: Sir, we have given assistance to set up small scale industries as also co-operative societies by grants-in-aid and also provide assistance for participating in equity, etc. Besides my Ministry, the Khadi and Village Industries Commission also provides assistance. Then there is a scheme called Mahila Udyog Nidhi for women entrepreneures. There is another recent scheme under SIDBI also. There are so many schemes for small units.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इनसेंटिव बताइए । . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, could you make out anything from this about incentives? Sir, could you understand?

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, आपको आ गया समझ में जवाब ? मुझे तो नहीं आया । अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरी बात है, मगर मुझे तो समझ में नहीं आया ।

MR. CHAIRMAN: Some help is being given and that much I can understand . . . (*Interruptions*) . . . Smt. Veena Verma.

श्रीमती वीणा वर्मा : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, हमारी भारतीय सरकार लिबरलाइजेशन पालिसी के अंतर्गत चाहे शहर हो या गांव, फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा दे रही है, उससे देश को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा भी होने जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन जैसे बहुत सी चीजों में हैल्थ-हैजार्डस तत्व पाए गए हैं । फूड प्रोसेसिंग में, जिस तरह कि चाकलेट में निकिल कंटेंट पाए जाते हैं, कोल्ड-ड्रिंक में भी कोई कैमिकल मिलाएंगे यह लोग, मैक्डॉवल में भी व्हिस्की या उस तरह की चीजें मिला रहे हैं, तो इस तरह से हैल्थ-हेजार्ड पर जो प्रोफिट कमाने का है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टरी का क्या इसके लिए कोई चैक, कोई रेगुलेशन, कोई एक्ट बना रहा है कि किस हद तक यह प्रोफिट कमाएंगे और लोगों की जो हैल्थ है उसको बिगाड़ेंगे ? मैंने पीछे कुछ समय पहले सवाल भी पूछा था कि चाकलेट में निकिल कंटेंट मिलाया जा रहा है, उसके जवाब में कहा गया था कि टेस्ट हो रहा है लेबोरेटरी में, तो उसके रिजल्ट क्या हैं ? क्या उसको चैक किया गया है ? क्या उसको रोका गया है ? या अभी तक उस तरह की स्थिति में है ? इनका जवाब मैं मंत्री जी से चाहती हूं ।

SHRI TARUN GOGOI: Sir, in fact, these things have to be covered under the Prevention of Food Adulteration Act. If there is any violation under this Act, they are liable to be prosecuted.

AN HON. MEMBER: How many have been prosecuted?

SHRI TARUN GOGOI: Nobody has brought any case to my notice. If you have anything, bring it to my notice and I will look into it. If you have any instance, whatever it may be, bring it to my notice and then I will go into it.

MR. CHAIRMAN: Shri Ajit Jogi

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, यह तो सही बात है कि सरकार ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं, मगर मेरा प्रश्न पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है, अभी जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उससे इस तरह की इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां आदिवासी इलाकों में लगें, इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था नहीं है । उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में रायगढ जिले के आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में टमाटर होता है, पर वहां पर टमाटर के फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई भी यूनिट नहीं लगा पा रहा है क्योंकि उसको हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं । तो मेरा प्रश्न मंत्री महोदय से यह है कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, जो आप सुविधा दूसरे क्षेत्रों में दे रहे हैं, उससे अधिक सुविधा दी जा सके ?

SHRI TARUN GOGOI: Sir, as regards tomato, it is not only in Madhya Pradesh but also in every State and even in my own State. I have already said that only slightly over one per cent is processed. The Ministry has started a scheme in order to provide assistance to the tribal areas. We provide grants upto 75 per cent to the tribal areas, North-East region and 50 per cent to the co-operative societies of other areas.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Sir, my supplementary was regarding the additional incentives provided in the tribal areas. Are you going to give some additional incentives? That was my supplementary.

SHRIMATI MIRA DAS: Sir, Honourable Finanne Minister in his Budge Speech has shown concern for the unprecendented economic crisis in the country. Sir, at the same time he talks of rapid employment generation, particularly in the rural areas. Food Processing industry is one area which can provide employment to millions in the rural areas. My request to the Minister is, whether he will try to get support or financial help from NABARD as NABARD is helping in rural development, to help weavers and other sectors also. Will he get such type of help from the NABARD so that the real dream of our Finance Minister can be fulfilled in this way?

SHRI TARUN GOGOI: This is the one of the industries which can generate large number of employment opportunities in the rural areas and benefit the farmers. In fact, NABARD can provide assistance for the Food Processing Industry to set up cold chains and some other infrasructural facilities.

Increase in the Import btll ofc crude oil and petroleum products

*126. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of PTEROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state·

(a) whether it is a fact that the Crude Oil and Petroleum Products import bill is estimated to touch $7.5 billions by the terminal year of the Eighth Five Year Plan;

(b) whether it is also a fact that by the turn of the century, the import bill will double to $14 bilions; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. *SATISH SHARMA*): *(a) to (c)*: A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The value of net import was 5.587 and 5.07 billion dollars in 1992-93 and 1993-94 respectively and it is estimated at 5.44 billion dollars in the current year.

Government have initiated a number of steps to increase indigenous production of crude oil. These include development of new oil and gas fields and additional development of some existing fields. Besides, promoting conservation of petroleum products in various fields, efforts are being made to increase the refining capacity by taking up expansion of existing refineries and by setting up of new grass-roots refineries in the public sector, joint sector and private sector in order to reduce expenditure on imports of petroleum products.

Therefore, it is extremely difficult presently to predict the impact of various factors like increase in demand of petroleum products, materialtsation of indigenous crude production plan and prices of crude oil and products in the international market, which affect the import bill.